बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 229

स्पष्ट हो जानकारी

सरकार निरंतर गहन होती मंदी के बीच राजकोषीय संकट का सामना करती नजर आ रही है। हाल में सामने आए आंकड़ों से केवल यही नतीजा निकलता दिखता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में सितंबर में लगातार दूसरे माह गिरावट नजर आई और यह 4.3 फीसदी गिर गया। इससे पहले अगस्त 2019 में इसमें 1.4 फीसदी की गिरावट देखने को मिली थी। सितंबर में आई गिरावट 2012 में आईआईपी की नई शृंखला लागू होने के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। इससे बड़ी गिरावट अक्टूबर 2011 में देखने को मिली थी जो 5 फीसदी की थी। यह वह दौर था जब वित्तीय संकट के बाद राजकोषीय प्रोत्साहन का आधार खत्म हो रहा था और भारत लंबी मंदी की ओर बढ़ रहा था। आईआईपी की अक्सर उसकी कमियों के कारण या कुछ क्षेत्रों के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रियावादी होने के चलते आलोचना की जाती है, लेकिन संभव है कि सकल घरेलू उत्पाद के दूसरी तिमाही के आंकड़े भी औद्योगिक उत्पादन में मंदी को परिलक्षित करें।

इस बीच सरकार ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के राजस्व और व्यय के आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। सरकार ने 27.86 लाख करोड़ रुपये के बजट व्यय में से 13.44 लाख करोड़ रुपये खर्च किए और 20.82 लाख करोड़ रुपये की बजट में उल्लिखित प्राप्तियों में से 8.37 लाख करोड़ रुपये मूल्य की प्राप्तियां हासिल हुईं। व्यय की गई राशि का अनुपात जहां अतीत के रुझानों से मेल खाता है, वहीं तथ्य यह है कि गत वर्ष राजस्व में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई थी। यही कारण है कि अंतिम बजट में उल्लिखित आंकड़ों की आलोचना करते हुए कहा गया था कि उनमें राजकोषीय घाटे की वास्तविक स्थिति सामने नहीं आती है क्योंकि वह सार्वजनिक क्षेत्र की उधारी की असल तस्वीर का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

सरकार ने अपने व्यय की वित्त व्यवस्था का कुछ दायित्व सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों पर डाल दिया जिन्होंने बाजार से उधारी ली थी। यदि राजस्व में अपेक्षा के अनुसार वृद्धि होती है तो भी इस वर्ष पुन: वैसी ही कवायद करनी होगी। इसका सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता पर और भी ज्यादा असर पड़ेगा।

बहरहाल, यदि कर संग्रह की चिंताओं को भी ध्यान में रखा जाए तो इस वर्ष की स्थिति पिछले वर्ष से भी अधिक खराब हो सकती है। इस समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के मुताबिक आयकर विभाग चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर लक्ष्य में कमी की मांग करेगा। यह मांग एक लाख करोड़ रुपये तक की कमी की हो सकती है। कॉर्पोरेट आय कर के वर्ष के दौरान 15 फीसदी तक बढ़ने की बात कही गई थी लेकिन अक्टूबर तक यह केवल 0.5 फीसदी बढ़ा है। व्यक्तिगत आय कर में वृद्धि 5 फीसदी के साथ अपेक्षाकृत बेहतर रही है। यह बात अलग है कि इसके लिए 22 फीसदी का लक्ष्य तय किया गया था। कॉर्पोरेट आय कर दरों में कटौती किए जाने के बाद बजट में तय लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रत्यक्ष कर में 30 फीसदी या इसके आसपास की वृद्धि हासिल करनी होगी जो लगभग असंभव प्रतीत होता है। सरकार ने कर अधिकारियों की आक्रामक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की बात कही है क्योंकि अतीत में वे कॉर्पोरेट रुझानों को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। परंतु वह लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या करेगी यह रहस्य बना हुआ है।

बजट निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सरकार के लिए बेहतर यही होगा कि वह देश की आर्थिक परिस्थितियों की स्पष्ट, पारदर्शी और सटीक तस्वीर पेश करे। ऐसा करके ही वह जरूरी विश्वास बहाली कर पाएगी। आंकड़े दुरुस्त नहीं हैं और यह हमें अभी भी दिखाई दे रहा है। बजट में वास्तविक स्थिति को छिपाया नहीं जाना चाहिए।

विनय सिन्हा

एनपीए की समस्या है दूरसंचार संकट

दूरसंचार क्षेत्र को लेकर अंतरिम राहत की घोषणा के बाद ढांचागत सुधारों को अपनाए जाने की आवश्यकता है। इस विषय पर विस्तार से दृष्टि डाल रहे हैं **श्याम पोनप्पा**

दूरसंचार क्षेत्र का वित्तीय तनाव समाप्त करने के लिए गठित सचिवों की समिति को इस क्षेत्र के बचे रहने के लिए तत्काल अंतरिम उपायों पर काम करना होगा। परंतु क्या केवल इसका बचे रहना देश के विकास और वृद्धि के लिए पर्याप्त होगा? क्या यह संभव है कि बाकी क्षेत्रों से अलग-थलग दूरसंचार क्षेत्र में सुधार किया जाए?

हालांकि सेवाओं का मूल्य न्यूनतम है लेकिन हमारी संचार आवश्यकताओं का ध्यान ठीक तरह से नहीं रखा जा रहा है। क्या हमारे अभागे नागरिकों और उपक्रमों के लिए कभी यह संभव होगा कि खराब सेवाओं और गंवाई जा रही उत्पादकता से परे अन्य देशों के साथ बराबरी कर सकें। यह संभव है बशर्ते कि हम बड़े ढांचागत बदलावों में सफल हों। इसकी शुरुआत दूरसंचार से होनी चाहिए। परंतु दूरसंचार क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए सरकार के साथ-साथ हम सभी को इस हकीकत को स्वीकार करना होगा कि जिस तरह वित्तीय कारक अर्थव्यवस्था को गति देते हैं, डिजिटलीकरण और संचार को उत्पादन और आपूर्ति के केंद्र में लाना होगा। दूरसंचार और डिजिटलीकरण बुनियादी ढांचा क्षेत्र तथा तमाम अन्य क्षेत्रों में नीतिगत रूप से सक्षम बनाने का काम करते हैं। दुनिया के प्रमुख देश इस क्षेत्र में आगे हैं और इतनी सक्षमता से काम कर रहे हैं कि हमारे लिए वह सोचना भी मुश्किल है। हमें उस राह को हासिल करने के लिए योजना बनानी होगी। बकाया भुगतान से छेड़छाड़, शुल्क में कमी और बदलाव आदि से हालात बदलने वाले नहीं हैं। इस लिहाज से समिति का दायरा बहुत सीमित है। वह केवल दर्द को कम कर सकता है जबकि जरूरत यह है कि इस उद्योग में नई जान फूंकी जाए।

अगर समिति का दायरा व्यापक होता तो क्या हम डिजिटलीकरण को विकास और वृद्धि के लिए अपनी मूल नीति बना सकते थे? चीन के दूरसंचार सुधारों पर आधारित एक अध्ययन को देखें तो सुधारों को लेकर उनका रुख सरकार के सार्वभौमिक कवरेज, संचालन और नियंत्रण तथा सक्षमता और उद्योग जगत की मुनाफा कमाने की कोशिश को संतुलित स्वरूप प्रदान करने का था। इसके साथ ही लोगों और उपक्रमों को अधिक मुक्त और तीव्र संचार की आवश्यकता थी। आज हमें भी इसकी आवश्यकता है।

सरकार, न्यायपालिका, प्रेस और उपभोक्ताओं को भी यह समझना और स्वीकार करना होगा कि दूरसंचार संकट फंसे हुए कर्ज की व्यापक समस्या का हिस्सा है। इसका संबंध एनपीए और बैंकिंग से है जो अचल संपत्ति और विनिर्माण, बिजली और सड़क तथा स्थिर और अनुमन्य करों से जुड़ा है। सरकार द्वारा भुगतान में देरी और कर आतंक पर रोक लगनी चाहिए। यथास्थिति बरकरार रखने से समस्या हल नहीं होगी। दूसरी बात यह कि जमा लेने वाले संस्थानों को भारतीय रिजर्व बैंक का नियमन मानना चाहिए। संकटकाल में विशेषज्ञता और क्षमता के साथ तत्काल कदम उठाने चाहिए ताकि परिसंपत्तियों और परिचालन का बचाव किया जा सके। जैसा सत्यम या आईएलऐंडएफएस के साथ हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि जमाकर्ताओं और कर्जदाताओं का काफी पैसा फंसा होता है। पंजाब ऐंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक जैसी अफसरशाही प्रक्रियाओं में परिणाम एक और जॉम्बी बैंक के रूप में सामने आता है जहां जीवित रहने के लिए जमाकर्ताओं का धन प्रयोग में लाया जाता है।

कमेटी का ध्यान नकदी प्रवाह, उसकी आवक और समय पर रहना चाहिए, न कि केवल रियायती आवक के तात्कालिक मूल्य पर। रोजगार का मुद्दा एक वैध चिंता है लेकिन इसमें स्थायित्व होना जरूरी है। इसके लिए समय पर पैसे की आवक आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता है तो समय पर नकदी समर्थन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि बिना स्थायी नकदी के सब्सिडी बरकरार रखना मुश्किल है। कुछ समस्याओं से निपटने के लिए नीतियों में विधायी बदलाव करना होता है।

बीएसएनएल और एमटीएनएल

बीएसएनएल और एमटीएनएल की बात करें तो एक हालिया आलेख यह बताता है कि क्योंकि इनमें नई जान फूंकने की कवायद बेमानी हो सकती है। इन कंपनियों पर हद से ज्यादा कर्ज है। सरकारों ने एयर इंडिया की तरह इनका इस्तेमाल भी बाजार बिगाड़ने के लिए किया है। इसके चलते छिड़ी कीमतों की जंग ने पूरे उद्योग को औंधे मुंह कर दिया।

एक विकल्प आकार कम करना और नया कौशल प्रदान करना है। या फिर शायद दोनों काम करने की आवश्यकता है। सुरक्षा और जनहित दोनों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाना चाहिए। इनका संचालन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाना चाहिए। इससे ऐसी नीतियां बनाने में मदद मिलेगी जिसमें स्पेक्ट्रम आवंटन बिना नीलामी के उपयोग आधारित भुगतान पर किया जा सकेगा। इसके अलावा वाईफाई को 60 गीगाहर्ट्ज और 6 गीगाहर्ट्ज तक विस्तारित किया जा सकेगा।

कमजोर वित्तीय तंत्र

समिति को वित्तीय संस्थानों को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल देने की जरूरत है। वित्तीय तंत्र उत्पादक गतिविधियों के लिए दूसरे दर्जे का बुनियादी ढांचा मुहैया कराता है। उन्हें पर्याप्त बुनियाद की आवश्यकता होती है जिसमें संचार, ऊर्जा, पानी कचरा, सीवेज परिवहन आदि की उचित व्यवस्था हो। घर, सुरक्षा और कानून व्यवस्था तो हैं ही। हालांकि हममें से अधिकांश लोग इसे हल्के में लेते हैं लेकिन इसमें दो राय नहीं कि ये बहुत अहमियत रखते हैं। सामाजिक अव्यवस्था और आर्थिक अपर्याप्तता के चलते इनके लिए जोखिम उत्पन्न हो गया है। इसके अलावा बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा आदि भी जरूरी हैं। तभी इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित लोग काम कर पाएंगे।

कुछ वर्ष पहले तक कमजोर बुनियादी ढांचे के बावजूद वित्तीय तंत्र हमारी असल ताकत था। हालांकि एनपीए की बढ़ती घटनाओं के कारण यह समय-समय पर नष्ट भी होता रहा। हालांकि इस क्षेत्र की पेशेवर क्षमता में मजबूती थी जिसने दबाव के बावजूद इसे थामे रखा। समय बीतने के साथ-साथ इन संस्थानों में गिरावट आई। इसमें अन्य बातों के अलावा ऋण की गुणवत्ता और एनपीए भी वजह था। अनुपालन में कमजोरी के कारण धोखाधड़ी के मामले पकड़े नहीं जा सके। इस दौरान नोटबंदी भी हुई और बीमा योजनाएं बेचने के दबाव ने भी असर दिखाया। सरकारों को इन चीजों को समझते हुए पेशेवर रुख उत्पन्न करना होगा।

समिति के दायरे का विस्तार करके दूरसंचार और डिजिटलीकरण के ऐसे लक्ष्य तय किए जा सकते हैं जो संचालन, उद्योग और उपयोगकर्ताओं के हित में हों। इस दिशा में काम करते हुए चीन तथा स्वीडन जैसे देशों से सीख ली जा सकती है। इसके साथ ही लिंकेज और एनपीए की समस्या से निपटा जा सकता है। शायद ऐसा करके हम मौजूदा गतिरोध वाले राजनीतिक रुख से दूरी बना पाएं।

सरकार के व्यय व प्राप्ति आंकड़ों से नहीं उभरती सही तस्वीर

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

वित्त वर्ष की पहली छमाही में व्यय एवं प्राप्तियों के आंकड़े सरकारी वित्त में तनाव को पूरी तरह नहीं दर्शाते हैं। तीन महीने से भी कम समय में सरकार अगले वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करेगी। उसके पास केवल कुछ हफ्ते ही रह गए हैं

वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही के केंद्र सरकार के राजस्व और व्यय आंकड़े जारी हो चुके हैं। अगर आप व्यापक प्रवृत्ति पर ध्यान दें और पिछले साल की समान अवधि की घटनाओं से तुलना करें तो आप यह मान सकते हैं कि हालात न केवल नियंत्रण में हैं बल्कि असल में कहीं बेहतर हुए हैं।

सरकार का कुल व्यय 13.44 लाख करोड़ रुपये रहा है जो समूचे वित्त वर्ष के 27.86 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान का 53.4 फीसदी है। आप यह दलील दे सकते हैं कि पहले छह महीनों में इस दर से खर्च करना सरकारी व्यय पर सख्त नियंत्रण को दर्शाता है। पिछले साल भी पहली छमाही में सरकारी व्यय 2018-19 के बजट अनुमान का 53.4 फीसदी ही रहा था।

जहां तक अप्रैल-सितंबर 2019 में सरकार की कुल प्राप्तियों का सवाल है तो इसके 8.37 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जो वित्त वर्ष के 20.82 लाख करोड़ रुपये के प्राप्ति अनुमान का करीब 40 फीसदी है। गत वर्ष की पहली छमाही में सरकार की कुल प्राप्तियां वित्त वर्ष के लक्ष्य का 39 फीसदी रही थीं।

ऐसे में आश्चर्य नहीं है कि 6.51 लाख करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य का 92.6 फीसदी पहुंच गया है। पिछले साल यह घाटा 95.3 फीसदी के ऊंचे स्तर पर रहा था।

लेकिन सरकार की वित्तीय सेहत में स्पष्ट सुधार के ऐसे चिह्न हमें गलत दिशा में भी ले जा सकते हैं। हमें याद रखना होगा कि पिछले साल सरकार का व्यय दबाव में था और कुछ देनदारियां अन्य सार्वजनिक इकाइयों को हस्तांतरित करने से उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपये की कमी आई थी। इसलिए ऐसा नजर आ सकता है कि इस साल भी कुछ वैसी ही कवायद की जाएगी क्योंकि वर्ष 2019-20 में सरकार का कुल व्यय 20 फीसदी से अधिक बढ़ोतरी के साथ 27.86 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। गत वित्त वर्ष में सरकार का वास्तविक व्यय 23.11 लाख करोड़ रुपये रहा था।

यह अभी साफ नहीं है कि सार्वजनिक इकाइयों को कितनी व्यय राशि हस्तांतरित की जानी है और किसे एक बजट-इतर उधारी के तौर पर चिह्नित किया जाएगा? लेकिन अभी तक का व्यय रुझान यही संकेत देता है कि पिछले साल की घटनाएं ही दोहराई जाएंगी।

चिंता का दूसरा क्षेत्र बड़ी सब्सिडियों पर सरकारी व्यय में छमाही रुझान के आधार पर है। सरकार ने वर्ष 2019-20 के समूचे साल के लिए खाद्य, उर्वरक एवं पेट्रोलियम सब्सिडी के मद में तीन लाख करोड़ रुपये खर्च का बजट लक्ष्य रखा था। लेकिन चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में ही 2.11 लाख करोड़ रुपये यानी 70 फीसदी राशि खर्च हो चुकी है। गत वर्ष की समान अवधि में सरकार ने 1.88 लाख करोड़ रुपये की अपेक्षाकृत कम राशि ही खर्च की थी लेकिन वह बजट अनुमान का 71 फीसदी था।

व्यय संपीडन के चलते सरकारी देनदारियों को सार्वजनिक इकाइयों के समूह को हस्तांतरित किया गया है। इस काम को प्रमुख सब्सिडियों के मद में अंजाम दिया गया है। अनुमानित सब्सिडी राशि का करीब 70 फीसदी हिस्सा पहले ही खर्च हो जाने से अगले कुछ हफ्तों में ही सब्सिडी का बोझ उठाने का जिम्मा सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय खाद्य निगम और पेट्रोलियम कंपनियों पर डाला जाने लगेगा। ऐसा होने की संभावना इसलिए है कि अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि सरकार अपने खातों को साफ करने की योजना बना रही है और बजट से अधिक सभी उधारियों को सरकारी उधारी का हिस्सा दिखाने वाली है ताकि राजकोषीय घाटे का सटीक स्तर परिलक्षित हो सके।

चिंता का तीसरा बिंदु सरकारी प्राप्तियों से जुड़ा हुआ है। सरकारी प्राप्तियों में स्वस्थ बढ़ोतरी काफी हद तक करीब 58,000 करोड़ रुपये के आरबीआई अधिशेष के एकमुश्त हस्तांतरण की वजह से है। विनिवेश के मोर्चे पर वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में रुझान अधिक उत्साहजनक नहीं हैं। इस दौरान केवल 12,400 करोड़ रुपये ही मिले हैं जबकि सरकार ने बजट में 1.05 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश राजस्व का लक्ष्य रखा था। सार्वजनिक इकाइयों में सरकार का हिस्सा बेचने से होने वाली विनिवेश आय का लक्ष्य हासिल करने के लिए बाकी बचे समय में एयर इंडिया एवं बीपीसीएल को बेचने का काम पूरा करना होगा।

कराधान के मोर्चे पर पहली छमाही में सकल कर राजस्व की वृद्धि घटकर महज 1.43 फीसदी दर के साथ 9.19 लाख करोड़ रुपये पर आ चुकी है। साल के पहले पांच महीनों में तो वृद्धि दर 4.25 फीसदी के स्तर पर थी। अप्रैल-सितंबर में भी कॉर्पोरेट कर वृद्धि गिरकर दो फीसदी रह गई जबकि अप्रैल-अगस्त की अवधि में यह करीब पांच फीसदी रही थी। व्यक्तिगत आयकर और सीमा शुल्क के संग्रह में भी ऐसी ही सुस्ती देखी गई है।

लिहाजा ऐसा लगता है कि वित्त वर्ष की पहली छमाही में व्यय एवं प्राप्तियों के आंकड़े सरकारी वित्त में तनाव को पूरी तरह नहीं दर्शाते हैं। तीन महीने से भी कम समय में सरकार अगले वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करेगी। उसके पास केवल कुछ हफ्ते ही रह गए हैं जिसमें वह अपनी वित्तीय स्थिति के तनाव को पारदर्शी ढंग से स्वीकार कर सकती है या फिर वह असली तस्वीर नहीं दिखाने वाले हेडलाइन घाटे के आंकड़े ही देना जारी रख सकती है।

कानाफूसी

तैयारी शुरू

उत्तर प्रदेश में सन 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी ढाई वर्ष की अवधि बची है। समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस पार्टी दोनों ने सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। परंतु भाजपा के लिए अच्छी बात यह है कि ये दोनों दल खुद को प्रमुख विपक्षी दल के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। जहां तक बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की बात है तो वह अपने दम पर कहीं भी मुकाबले में नहीं दिख रही है। सपा और बसपा ने लोकसभा चुनाव साथ लड़ा था लेकिन खराब प्रदर्शन के बाद उसने अचानक गठबंधन तोड़ लिया था। हालिया विधानसभा उपचुनाव में सपा को तीन सीटों पर जीत मिली जबकि बसपा को एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस उपचुनाव में खाता खोल पाने में नाकाम रही लेकिन उसका प्रदर्शन बसपा से अच्छा रहा। वह दो सीटों पर दूसरे स्थान पर रही और पांच सीटों पर बहुत मामूली अंतर से तीसरे स्थान पर रही। सपा ने पहले ही यह घोषित कर दिया था कि वह उपचुनाव अकेले लड़ेगी। यह बात उसके हक में साबित हुई। कहा जा सकता है कि वह अगर इसी नीति पर कायम रही तो वह अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने में कामयाब रहेगी।

आपका पक्ष

आधुनिकीकरण से कृषि होगी उन्नत

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने कहा है कि भारत में वर्ष 2016 में 11,379 किसानों ने आत्महत्या की। यह आंकड़ा एनसीआरबी की 2016 की एक्सिडेंटल डेथ ऐंड सुसाइड रिपोर्ट में सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, हर महीने 948 या हर दिन 31 किसानों ने आत्महत्या की। इससे पहले वर्ष 2015 में इससे जुड़ी रिपोर्ट जारी की गई थी। हालांकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि साल दर साल आत्महत्या के मामलों में कुछ कमी आई है। वर्ष 2016 में 11,379 किसानों ने, 2014 में 12,360 और 2015 में 12,602 किसानों ने आत्महत्या की थी। हालांकि ताजा रिपोर्ट में आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं की गई है। देश में कृषि क्षेत्र की जिम्मेदारी राज्य के अंतर्गत आती है फिर भी राज्यों के अलावा केंद्र सरकार भी किसानों के उत्थान के लिए योजनाएं बनाती हैं। इनके बावजूद देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं यह अफसोस की बात है। किसान आत्महत्या की वजह फसलों की बरबादी, बीमारी, पारिवारिक कठिनाई एवं कर्ज आदि हैं। किसानों पर मौसम की मार भी पड़ती रहती है। कभी

अधिक बारिश होने के कारण किसानों की खड़ी फसल खेतों में ही बरबाद हो जाती है। कभी सूखे के कारण फसल सूख जाती हैं। इसके अलावा ओले पड़ने से भी फसल बरबाद होने की खबरें आती हैं। किसान आज भी सिंचाई के लिए मॉनसून पर ही निर्भर है ओर खेती के लिए मॉनसून का इंतजार करते हैं। हालांकि सरकार ने राष्ट्रीय कृषि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सिंचाई योजना जैसे

देश में कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने के लिए किसानों को उचित सुविधाएं मुहैया कराने की जरूरत है

कार्यक्रम चलाए हैं। इनसे कृषि उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन किसानों की आय में उनके परिश्रम और अपेक्षा के अनुरूप बढ़ोतरी नहीं हो रही है। देश में सीमांत एवं लघु किसान और खेतिहर मजदूरों की हालत दयनीय है। इनके उत्थान के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम नाकाफी हैं। कृषि उत्पादों का उचित भाव नहीं मिलना यह कृषि क्षेत्र से जुड़ी परिवारों की गरीबी का मुख्य कारण है। खाद, बीज, पशुओं के खाद्य से संबंधित वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं जिसका प्रतिकूल असर उनकी आय में पड़ रहा है। भूमि की कम उत्पादकता, असिंचित क्षेत्र, मॉनसून पर निर्भरता, जलवायु परिवर्तन, कृषि वित्त का अभाव जैसे अनेक सवाल कृषि क्षेत्र के समक्ष खड़े हैं। इसके अलावा कृषि निवेश जीडीपी का मात्र 2 प्रतिशत है। देश के विकास के लिए कृषि क्षेत्र का योगदान महत्त्वपूर्ण है। इसलिए सरकार को किसानों की आत्महत्या रोकने और उनके उत्थान के लिए कृषि क्षेत्र में बदलाव एवं आधुनिकीकरण के कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा सरकार को किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के उपाय खोजने चाहिए जिससे उनकी आय दोगुनी हो सके।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

ऐतिहासिक निर्णय के बाद चुनौतियां

राम मंदिर मामले में शीर्ष न्यायालय के 9 नवंबर के निर्णय के बाद अयोध्या एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। अब अयोध्या के समक्ष मुख्य चुनौती तीव्र आर्थिक विकास की है। इसके बिना अयोध्या को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल का स्वरूप देना संभव नहीं है। अयोध्या में अब सिर्फ भव्य मंदिर ही नहीं बल्कि एक भव्य मस्जिद को भी साकार रूप देना है। इसलिए अयोध्या के सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक इन्फ्रास्ट्रक्चर दोनों के तीव्र गति से विकास की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से अयोध्या को सड़क, रेल और वायुमार्ग से देश के अन्य क्षेत्रों में बेहतर संपर्क देने की जरूरत है। दूसरी बड़ी चुनौती साफ-स्वच्छ अयोध्या की है। अयोध्या में सभी धर्म के लोग रहते हैं और यह उन सभी के लिए पवित्र स्थल की तरह है। अत: अयोध्या में एक निश्चित समय सीमा में मास्टर प्लान बना कर अमल करने की जरूरत है जिससे अयोध्या विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बना सके।

देवांशु विक्रम सिंह, अयोध्या

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।